पाँचवा-स्तम्भ

30 1983 2012 CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 15, अंक 4/2014

बिजली चोरी रोकने के लिए उठाने होंगे ठोस कदम!

'कट्स' की ओर से जयपुर में बिजली चोरी से होने वाली परेशानियों व इससे आम उपभोक्ता व सरकार को होने वाले नुकसान का जायजा कराने के मकसद से 'कटियाबाज' फिल्म दिखाई गई। दीप्ती कक्कड़ और फहाद मुस्तफा निर्देशित इस फिल्म में कानपुर शहर में दिवालिया हो चुकी विद्युत वितरण कंपनी व शहरवासियों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है।

फिल्म में एक महिला अधिकारी और एक विद्युत चोर ने अपने-अपने ढंग से विद्युत कम्पनी के दिवालियापन को एक संघर्ष के रूप में उजागर किया है। इस फिल्म का बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलावा विश्वभर के करीब 50 समारोहों में प्रदर्शन हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है।

राज्य का ऊर्जा विभाग आज भी तकनीकी हानि के बढ़ते ग्राफ से जूझ रहा है। वर्ष 2008 से 2013 के मध्य मात्र बिजली चोरी के कारण सरकार को जो तकनीकी हानि हुई उसकी कीमत 70 हजार करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली की तकनीकी हानि जो वर्ष 2012-13 के दौरान 18.39 फीसदी थी वह वर्ष 2013-14 में 21.03 फीसदी तक पहुंच गई है। कार्यक्रम के दौरान हुई पैनल चर्चा में यह तथ्य सामने आए, जिसमें खासतौर पर यह उभर कर आया कि बिजली चोरी का खामियाजा निर्दोष व ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। बिजली चोरी रोकने के लिए यदि सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आगे नहीं आ सकेगा।

पैनल चर्चा में मुख्य वक्ताओं में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अभियांत्रिकी निदेशक आर.सी.शर्मा, राजस्थान ऊर्जा विभाग के सलाहकार आर.जी गुप्ता, नियामक आयोग के पूर्व तकनीकी सदस्य के.एल.व्यास, हरदेव जोशी पत्रिकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति सन्नी सेबस्टेन, वरिष्ठ मीडिया पर्सन राजेन्द्र बोरा तथा सोडा (टोंक) की सरपंच छवि राजावत के अलावा विद्युत क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान अनेक वक्ताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बिजली चोरी में जयपुर का 9वां नम्बर

जयपुर, धौलपुर व झालावाड़ बिजली चोरी के गढ़ बन गए हैं। धौलपुर में जहां करीब आधी बिजली चोरों के हवाले है, वहीं पिछले एक साल में झालावाड़ में बिजली छीजत 18 फीसदी तक बढ़ गई है। चालू वर्ष में यह आंकड़ा और बढ़ता नजर आ रहा है।

बिजली चोरी में जयपुर जिले का राज्य में 9वां नम्बर है। जबकि कंगाली के कगार पर खड़ी बिजली कंपनियां मूकदर्शक बनी हुई हैं। न तो बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और न ही फिसड्डी फील्ड अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों की वार्षिक बैठक में पेश वर्ष 2013-14 के सर्किटवार प्रगति रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

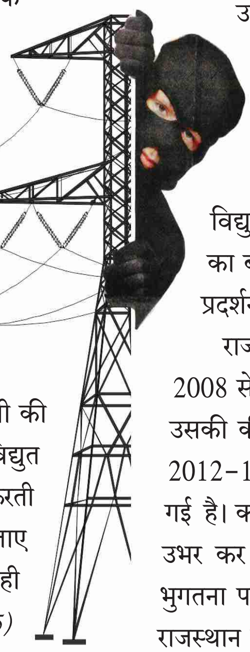

दरअसल, बिजली चोरी का सीधा खामियाजा आम निर्दोष उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। बिजली चोरी से हो रहे आर्थिक नुकसान को कंपनियां अपने वार्षिक लेखों में घाटे के रूप में प्रदर्शित करती हैं और फिर उसी को आधार बना कर बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करती है। ऐसे में अगर बिजली चोरी रुक जाए तो बिजली महंगी करने की नौबत ही नहीं आए। *(रा.प., 17.01.15)*

इस अंक में...

- पेंशन में 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा 3
- भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार 5
- खराब मीटर पर 5 फीसदी छूट 8
- तेजी से गिरता भूजल स्तर 9
- अब सबको मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ ... 11

प्रदेश में 96 फीसदी किसान जैविक खेती अपनाने के लिए तैयार

'कट्स' द्वारा 'स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन' के सहयोग से संचालित प्रोओर्गेनिक परियोजना के तहत 13 नवम्बर को जयपुर में हितधारकों की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य परियोजना के तहत जैविक उत्पादों के उपभोग और उत्पादन की धरातल स्तरीय वास्तविकता ज्ञात करने के लिए किए गए अध्ययन का विवरण प्रस्तुत करना था। परियोजना राज्य के छह जिलों जयपुर, दौसा कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में संचालित की जा रही है।

परियोजना अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों के अनुसार 78 फीसदी उपभोक्ताओं को रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी है तथा महिलाओं में मात्र 28 फीसदी महिलाएं ही जागरूक हैं। करीब 93 फीसदी उपभोक्ताओं ने जैविक उत्पादों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभावों से 91 फीसदी किसान वाकिफ हैं तथा इतने ही फीसदी किसान जैविक खाद्य पदार्थों को बेहतर मानते हैं। करीब 96 फीसदी किसान अनुदान प्राप्त होने व उत्पादों का उचित मूल्य मिलने पर जैविक खेती अपनाने के लिए तैयार है। केवल 25 फीसदी किसानों को नाबार्ड द्वारा संचालित किसान क्लब के बारे में पता है।

बैठक में कृषि विभाग के निदेशक, डॉ. शीतल प्रसाद; कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा के डॉ.एस.एस यादव; स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन की प्रतिनिधि सारा नेल्सन; कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक, डॉ. एस.एस. राठौड़; कट्स निदेशक, जॉर्ज चेरियन; स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के कृषि एवं खाद्य विभाग; दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण तथा जैविक खेती पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शहरी सुशासन पर परिचर्चाओं की श्रृंखला

'माई सिटी' परियोजना के तहत जयपुर में परिचर्चाओं का आयोजन किया गया जिसमें चयनित जन प्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। 27 नवम्बर, 2014 को स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शहरी शासन के मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया और सेवाओं के स्तर में सुधार में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने विषय पर अपने विचार व अनुभव व्यक्त किये। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से फीडबैक लेने हेतु परिचर्चा बैठक बहुत लाभदायक रही।

30 दिसम्बर, 2014 को जयपुर शहर के नव निर्वाचित पार्षदों के साथ परिचर्चा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों के अलावा परियोजना में सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पार्षदों से चर्चा की। पार्षदों ने परियोजना के बारे में अपने विचार बताएं तथा संस्थाओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। पार्षदों ने 'माई सिटी' परियोजना में रूचि दर्शाई तथा इसे उनके वार्ड में लागू करने के लिए कहा। उन्होंने परियोजना के सफल क्रियान्वयन में सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

इसी श्रृंखला में, 31 दिसम्बर, 2014 को जयपुर नगर निगम के अधिकारीगणों के साथ परिचर्चा बैठक आयोजित की गई जिसमें जगदीश शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक ने नागरिकों की भागीदारी हेतु प्रयास के लिए 'माई सिटी' परियोजना की प्रशंसा की। अन्य अधिकारियों ने भी परियोजना की प्रशंसा की तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। संस्थाओं ने अधिकारियों से वार्ड स्तर की मीटिंग में उनकी न्यूनतम भागीदारी पर चिंता व्यक्त की तथा वार्ड स्तर की सभा में भाग लेने का आग्रह किया। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे वार्ड स्तर की सभाओं में उपस्थित होंगे।

कहां है जनता से वसूला फायर सेस?

फायर ब्रिगेड को मजबूत करने और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के 4 अक्टूबर 2013 को जारी निर्देशों के बाद एक साल से नगर निगम और जेडीए जनता से फायर सेस वसूल कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही विभागों ने वसूली गई लाखों रुपए की राशि के लिए न तो कोई फंड बनाया और न ही इस राशि से दमकलें और अन्य संसाधन खरीदे।

जयपुर जिस हिसाब से विकसित हो रहा है उसके हिसाब से फायर ब्रिगेड नहीं है। आये दिन अग्नि दुर्घटना के हादसे हो रहे हैं। दीपावली के दिन ही शहर में 65 स्थानों पर आगजनी की दुर्घटनाएं हुई लेकिन संसाधनों की कमी के चलते फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। *(दै.भा., 27.10.14)*

रुक गई करोड़ों रुपए की मदद

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र से आने वाली करोड़ों रुपए की सहायता राशि चार साल से प्रदेश को मिलना बन्द हो गई है। जल संसाधन विभाग ने योजना के प्रति इतना सुस्त रवैया रखा कि वर्ष 2009-10 में मिली 14.17 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया।

विडम्बना की बात तो यह भी है कि विभाग इससे अनजान है तथा राज्य सरकार की ढिलाई तक से इनकार कर रहे हैं, वहीं जल संसाधन मंत्री राम प्रताप को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में यह सच उजागर हुआ है। *(रा.प., 14.12.14)*

कचरा पात्र भी नहीं छोड़ा

श्री योजना के तहत गांवों में कचरा प्रबंधन के नाम पर एक संस्था मनमाने दामों पर पंचायतों में कचरा संग्रह पात्र रखवा रही है। बिना टेंडर और ग्रामसभा में अनुमोदन के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र की कई पंचायतों में जयपुर की श्री जवाहर खादी ग्रामोद्योग समिति की ओर से 10-10 कचरा पात्र भेजे जा चुके हैं। प्रति कचरा पात्र की कीमत 22,743 रुपए है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय कारीगर सात हजार रुपए प्रति कचरा पात्र की लागत में बनाकर देने का दावा कर रहे हैं। इस गड़बड़झाले का जब खुलासा हुआ तब यह सामने आया की अधिकारी भी अनभिज्ञ थे। *(रा.प., 26.11.14)*

पेंशन में 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ढाई लाख फर्जी लोगों को 150 करोड़ रुपए बांट दिए। यह खुलासा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सत्यापन जांच में हुआ है।

राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साल अगस्त में वृद्धावस्था पेंशन के प्रावधानों में बदलाव किया था। इससे करीब 57 लाख नए लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। इनमें ढाई लाख नाम ऐसे हैं, जिन्हें या तो दोहरी पेंशन मिल रही है या जिनके पते फर्जी हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फर्जी तरीके से बांटी गई इस राशि की वसूली होनी चाहिए। *(रा.प., 02.11.14)*

सोलर लाइट खरीद में गड़बड़ी

जयपुर जिले की 169 ग्राम पंचायतों को सोलर लाइट खरीद मामले में चार्जशीट दी जाएगी। चार्जशीट के साथ ही सरपंचों व ग्राम सेवकों को घोटाला राशि की रिकवरी के नोटिस भी थमाए जाएंगे। पंचायतीराज चुनाव से पहले ही जिले की 169 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का झटका भी लग सकता है।

जांच में सामने आया है कि जिले की 489 में से 169 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग करते हुए मनमर्जी से सोलर लाइटें खरीद ली। सरकार के निर्देश पर जिला परिषद में हुई विशेष जांच में यह खुलासा हुआ है। इन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, तकनीकी अधिकारियों में करीब 8.7 करोड़ रुपए रिकवरी निकाली है। *(दै.भा., 16.12.14, 24.12.14)*

योजनाओं पर खर्च की रफ्तार धीमी

विकास योजनाओं पर पैसा खर्च करने में विभागों की सुस्त रफ्तार के चलते उनके लाभ आम जनता को समय पर नहीं मिल पाते। चालू वित्त वर्ष के लिए 70 हजार करोड़ रुपए के योजनागत बजट में से अक्टूबर माह तक 27 हजार करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। शेष 43 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सिर्फ पांच महीने बाकी बचे हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में तय समय पर प्रस्ताव नहीं भेजे गए, तो पैसा नहीं मिल पाएगा।

सरकार की योजनाओं में फिलहाल सबसे ज्यादा अनदेखी कृषि, उद्योग व विज्ञान में हुई है। बजट में कृषि पर 4234 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है लेकिन अक्टूबर तक 837 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। उद्योग में 583 करोड़ के बजट की एवज में 99 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। *(दै.भा., 27.11.14)*

फर्जी बिलों से पैसा हजम

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हुनर से रोजगार तक' में बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पाली कार्यालय को क्षेत्रीय युवाओं को होटल में खाना बनाने, रख-रखाव और ग्राहकों की सेवा उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2013-14 में 33.50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

कर्मचारियों ने इस राशि से करीब 390 युवाओं को प्रशिक्षित करने का झूठा रिकॉर्ड पेश कर 23 लाख 50 हजार रुपए के फर्जी बिलों के द्वारा भुगतान उठा लिया। बाकी बचे 10 लाख के बिल भुगतान के लिए पेश कर रखे हैं, जिनका भुगतान रोका हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली शिकायत पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कराई गई जांच में यह घोटाला सामने आया। *(रा.प., 27.10.14)*

करोड़ों खर्च, प्लांटेशन का पता नहीं

प्रदेश में अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में घटता वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नाबार्ड पौषित आरआई डीएफ परियोजना के चलते सघन वृक्षारोपण व जलग्रहण क्षेत्रों के विकास का ध्येय वन विभाग के कुप्रबंधन के चलते पूरा होते नजर नहीं आ रहा। योजना के तहत वन विभाग को 2012-13 में 5 साल के लिए 336 करोड़ रुपए दिए गए थे, पर विभाग ने 17 जिलों में दो साल में प्लांटेशन पर 232 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन यह प्लांटेंशन कैसे और कहां किया गया इसकी जानकारी तक नहीं है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से वन विभाग की पहली बैठक में इस पर नाराजगी भी जताई जा चुकी है। वन मंत्री राज कुमार रिणवा ने कहा है कि सरकार परियोजना के तहत कागजों में पेड़ लगाने, बरती गई लापरवाही और आला अफसरों की मॉनिटरिंग की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। *(दै.भा., 22.11.14, 24.11.14)*

सोलह कलेक्टरों की परफॉर्मेंस जीरो

राज्य के 33 में से 16 कलेक्टर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जीरो है। चीफ सेक्रेट्री द्वारा नवम्बर में मुख्यमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। गांवों में जन सुनवाई और समस्याओं के निस्तारण के लिए कलेक्टर्स के गांवों के दौरे, निरीक्षण और नाइट स्टे जैसे मापदंड इस रिपोर्ट के आधार बिन्दु हैं। निर्देशानुसार कलेक्टरों को गांवों में महीने में कम से कम तीन नाइट स्टे करना और गांवों का पांच बार निरीक्षण व पांच दिन गांवों में दौरे करना अनिवार्य है।

रिपोर्ट के मुताबिक 16 कलेक्टर्स ने महीने में एक भी दिन गांवों में नाइट स्टे नहीं किया। इनमें से पांच कलेक्टर तो 30 दिन में एक भी दिन गांवों में गए ही नहीं। केवल नौ कलेक्टर्स ने तय दिन से ज्यादा परफॉर्मेंस दी है।

(दै.भा., 05.12.14)

पर्यावरण पर नहीं एक पैसा खर्च

वन विभाग के आला अफसरों की लापरवाही और उदासीनता के चलते बीसलपुर बांध बनने से पर्यावरण संतुलन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आया पैसा बैंक में दोगुना होने की स्थिति में है, लेकिन विभाग ने पर्यावरण संतुलन के नाम पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया।

सिंचाई विभाग ने बीसलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेबीटॉट सुधार के लिए 2005 में 3.5 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद 3.17 करोड़ रुपए और भेजे गए। वन विभाग ने पैसा मिलने के सात साल बाद 2012 में तो कार्ययोजना तैयार की, लेकिन आज तक वह मंजूर नहीं हो पाई। *(रा.प., 27.10.14)*

करोड़ों की दवाएं कबाड़ में

उदयपुर की एक धर्मशाला के हॉल में पड़ी अवधि पार दवाइयों ने एमबी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी है। दरअसल अवधि पार हुई दवाइयों की मात्रा राज्य सरकार में मानदंडों से 15 गुना अधिक है। एमबी अस्पताल प्रशासन, औषधि भण्डार के नोडल अधिकारी और स्टोरकीपर की लापरवाही से तीन साल में 1.60 करोड़ रुपए की दवाएं अवधि पार हुई।

सरकार के मानदंड के अनुसार कुल दवाओं की कीमत की 0.5 प्रतिशत खराब (टूट-फूट, अवधि पार) होना निश्चित है। चिकित्सालय को तीन साल में 20 करोड़ की दवाइयां भेजी गई थी उनमें से सिर्फ 10 लाख की दवाइयां ही अवधि पार या खराब होनी चाहिए थी। इसके उलट एक करोड़ साठ लाख रुपए की दवाइयों की बर्बादी हुईहै।

(रा.प., 21.11.14)

नरेगा: बकाया अदायगी में देरी क्यों?

मनरेगा कार्यों के तहत 22 करोड़ रुपए से अधिक की बकायादारी है, जिसे अदा करने में अफसरों की सुस्ती सामने आई है। मास्टररोल और व्यय के बिलों के भुगतान के 1004 और 5773 मामले हैं, जिनमें अभी तक भुगतान अदायगी नहीं हुई है।

राज्य के पिछड़े इलाकों में शामिल जिलों में बिलों का भुगतान नहीं होने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए है। जिनमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के अलावा राजसमंद, पाली, नागौर, जयपुर, अजमेर, करौली, जोधपुर और जैसलमेर जिले शामिल हैं। इन देन-दारियों को अदा नहीं करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काफी नाराजगी जता चुका है। *(दै.न., 27.12.14)*

मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक कब?

नई सरकार को सत्ता में आए नौ माह से ज्यादा समय बीत गया, पर मंत्रियों की संपत्ति अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के तहत प्रदेश में लागू केन्द्र की आचार संहिता के हिसाब से मंत्रियों को अपनी संपत्ति की घोषणा 13 फरवरी तक करनी थी, क्योंकि मंत्रियों ने पिछले वर्ष 13 दिसम्बर को शपथ ली थी। आचार संहिता के मुताबिक मंत्री बनने के दो महीने के भीतर संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी है।

आचार संहिता के तहत मंत्रियों को अपनी व परिजनों के स्वामित्व की अचल संपत्ति, नकद, जेवर व शेयर आदि चल संपत्तियों व देन-दारियों का ब्योरा मुख्यमंत्री या सामान्य प्रशासन विभाग को देना था। *(रा.प., 03.10.14)*

केन्द्र से मिला पैसा नहीं हुआ खर्च

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2014-15 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 20 लाख रुपए मिले। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते राशि के खर्च नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं।

वर्ष 2013-14 में भी केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे। इसमें से भी केवल 7.79 लाख रुपए ही विभाग खर्च कर पाया। यही नहीं हर साल व्यय की जाने वाली राशि का ग्राफ घटता जा रहा है। *(दै.भा., 04.11.14)*

भ्रष्टाचार में अव्वल है राजस्थान

प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के नजरिए से राजस्थान देश में सबसे आगे है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से जारी आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है। वर्ष 2012 के जो आंकड़े विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, उनसे यह पता चलता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सबसे अधिक 567 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं।

इसके बाद 526 मामले महाराष्ट्र में तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा जहां 426 मामले दर्ज हुए। चौथे स्थान पर ओड़िशा व पांचवें स्थान पर पर मध्यप्रदेश रहा जहां क्रमशः389 व 265 मामले दर्ज हुए हैं।

अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में लंबित मामलों की संख्या भी कई गुना अधिक देखी गई है। इसका यह मायने हुआ कि प्रदेश में सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में कार्रवाई की अनुमति देने की प्रक्रिया काफी धीमी है।

(न.नु., 10.11.14)

भ्रष्टाचार मुक्त मंत्रालय की मुहिम

विभिन्न सरकारी महकमों में जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुहिम तेज कर दी है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने नए फरमान में सभी मंत्रालयों को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने और सभी को भ्रष्टाचार विरोधी एंटी ब्राइबरी हॉट लाइन से जोड़ने का निर्देश दिया है।

इस व्यवस्था में सभी विभागों को एंटी ब्राइबरी टोल फ्री नम्बर जारी करना होगा। इस पर भ्रष्टाचार से परेशान कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। मंत्रियों व मंत्रालयों का आकलन करते समय मोदी यह भी देखेंगे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में संबंधित मंत्रालय कितना गंभीर रहा है।

(रा.प., 06.10.14)

काला धन वापस लाकर रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और इस मामले में सरकार सही दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार काला धन वापस लाने के प्रयासों में कोई कोताही नहीं बरतेगी।

उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए शुरू की गई मन की बात श्रृंखला के दूसरे अंक में काले धन के बारे में विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि अपने प्रधान सेवक पर भरोसा रखिए और अपने सुझाव फेसबुक, ट्वीटर और ई-मेल से अथवा चिट्ठी लिखकर भिजवाएं।

(दै.न., 03.11.14)

निगम सीईओ पर लगाया जुर्माना

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने पर जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर राजस्थान सूचना आयोग ने 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हरमाड़ा निवासी अशोक कुमार शर्मा द्वारा मांगी गई सूचनाएं नगर निगम के सीईओ ने निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराई। इस पर शर्मा ने सूचना आयोग में परिवाद दायर किया।

सूचना आयोग के भेजे गए नोटिस का जवाब भी सीईओ ने नहीं दिया और न ही किसी तरह का उत्तर सूचना आयोग के पास भेजा। मामले की सुनवाई पर मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन ने कहा कि अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी। ऐसे में आयोग की शक्ति के तहत अधिकतम 25000 रुपए का जुर्माना लगाना बेहतर होगा।

(दै.भा., 09.10.14)

भ्रष्टाचार-रोधी नीति की कमी

उद्योग मंडल सीआईआई और एलायंस फॉर इंटीग्रिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 'एक भ्रष्ट प्रतिस्पर्धी के हाथों ठेका गंवाने से कारोबार करने की लागत प्रभावित होती है।'

करीब 84 फीसदी लोगों का सोचना है कि भ्रष्टाचार-रोधी कार्यक्रम की कमी का कारोबार करने की लागत पर नकारात्मक असर होता है। सर्वेक्षण में 69 फीसदी लोगों का मानना है कि कंपनियां भारत में भ्रष्टाचार-रोधी नियमन के बारे में पर्याप्त रूप से वाकिफ नहीं है। सर्वेक्षण में 64 फीसदी लोगों ने कहा कि देश में आसान पहुंच वाली भ्रष्टाचार-रोधी नीति की कमी, भ्रष्टाचार घटाने की मुख्य चुनौतियों में से एक है। *(न.नु., 11.12.14)*

रिश्वत देकर चलाते हैं खटारा बसें

जयपुर शहर की मिनी बस यूनियन के अध्यक्ष यासीन ने खुलासा किया है कि बेखौफ चल रही खटारा मिनी बसों के पीछे पुलिस की मासिक बंधी और परिवहन विभाग में रिश्वतखोरी जिम्मेदार है।

एक ओर जहां पुलिस ने बस संचालकों से हर महीने की बंधी बांध रखी है वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग में हर बस को फिटनेस प्रमाण-पत्र देने के एक हजार रुपए ले रहे हैं। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अमर सिंह का भी कहना है कि पुलिस ऑटो वालों से पैसे वसूलती है।

(रा.प., 10.11.14)

भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार

देश में इस साल भ्रष्टाचार में कमी आई है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 175 देशों की सूची में भारत अब 85वें नम्बर पर आ गया है। भारत को 100 में से 38 अंक दिए गए हैं। पिछले साल हम 94वें स्थान पर थे और 100 में से 36 अंक मिले थे। चीन को 36 अंक मिले हैं और 18 साल में पहली बार हम चीन से कम भ्रष्ट निकले हैं। वह इस साल 80वें स्थान से 100वें स्थान पर खिसक गया ।

अमेरिका 74 अंक के साथ 17वें स्थान पर है। डेनमार्क 92 अंकों के साथ 2014 में सबसे कम भ्रष्ट देश रहा। पाकिस्तान और नेपाल को संयुक्त रूप से 126वां स्थान मिला है। जबकि उत्तरी कोरिया और सोमालिया सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहे हैं। सूचकांक में कम अंक देश में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है, जबकि अधिक अंक का मतलब भ्रष्टाचार का कम होना है।

(रा.प. एवं दै.भा., 04.12.14)

बतानी होगी आवेदन निरस्त करने की वजह

केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के मकसद से लोक सूचना अधिकारियों को नई हिदायतें दी हैं। अब किसी आवेदन को निरस्त करने के कारण का उल्लेख करते हुए उन्हें आवेदक को यह भी बताना होगा कि वह इसकी अपील किस अधिकारी के समक्ष कर सकेगा। साथ ही उन्हें आवेदक को निम्न जानकारी भी देनी होगीः

- लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर और ईमेल आईडी।
- आवेदन निरस्त करने पर सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की उस धारा का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करना होगा कि किस धारा के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
- यदि चाही गई सूचना किसी अन्य कार्यालय या अधिकारी से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसा आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित कर उसकी सूचना आवेदक को देनी होगी।

- जवाब के अन्त में यह स्पष्ट करना होगा कि यदि आवेदक लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह जवाब प्राप्ति के 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष नम्बर, ईमेल आईडी का अंकन जवाब में करना होगा।
- सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों पर लोक सूचना अधिकारी को हस्ताक्षर कर अपने पदनाम की सील लगाकर दिनांक अंकित करनी होगी। *(दै.न., 21.11.14)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
भीलवाड़ा	ओमप्रकाश पारीक	तकनीकी सहायक, अजमेर विद्युत वितरण निगम	15,000	*रा.प. एवं दै.न., 09.10.14*
जयपुर	जितेन्द्र बहादुर पाल	निरीक्षक, परिवहन विभाग, नीम का थाना, जयपुर	25,000	*रा.प., 10.10.14*
गंगानगर	दयाराम गोदारा	पटवारी, पदमपुर, श्रीगंगानगर	50,000	*रा.प., 10.10.14*
झालावाड़	जगदीश चन्द मेवाड़ा	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड़	10,000	*रा.प. एवं दै.न., 11.10.14*
जयपुर	डॉ.धनंजय मीणा	चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई	10,000	*दै.भा. एवं रा.प., 11.10.14*
कोटा	विमल जैन	शाखा प्रबन्धक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अरण्डखेड़ा	10,000	*रा.प., 21.10.14*
जयपुर	हासम खान	सब इंस्पेक्टर, महामंदिर थाना, जोधपुर	50,000	*दै.भा. एवं रा.प., 02.11.14*
बीकानेर	शिवरतन भाटी	इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स विभाग, बीकानेर	25,000	*रा.प. एवं दै.भा., 04.11.14*
बीकानेर	किशनलाल शर्मा	मैनेजर, मरुधरा ग्रामीण बैंक, दंतौर शाखा	15,000	*रा.प. एवं दै.न., 04.11.14*
हनुमानगढ़	पतराम साहिब राम	वरिष्ठ लिपिक, कृषि उपज मण्डी, पीलीबंगा सुपरवाईजर, कृषि उपज मण्डी, पीलीबंगा	1,00,000	*दै.न., 12.11.14*
उदयपुर	संजय बया	पटवारी, पटवार हल्का सवीना	5,000	*दै.न., 12.11.14*
जोधपुर	लालाराम	मुख्यआरक्षी, पुलिस थाना, फलसूण्ड	5,000	*रा.प. एवं दै.न., 14.11.14*
टोंक	मनोहरलाल जाट	अधिशासी अधिकारी, देवली नगर पालिका	1,00,000	*दै.भा एवं रा.प., 28.11.14*
बारां	बृजराज सिंह	एएसआई, कोतवाली, बारां	5,000	*दै.भा., 11.12.14*
भरतपुर	जवाहर सिंह गुर्जर	वरिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति कार्यालय, नगर	2,500	*दै.न., 13.12.14*
जयपुर	मूलचंद सैनी	एसआई, शाहपुरा थाना, जयपुर	10,000	*रा.प. एवं दै.भा., 14.12.14*
डूंगरपुर	बहादुर सिंह	लाइनमेन, जेवीवीएनएल, स. अभियंता कार्यालय	2,000	*रा.प. एवं दै.न., 17.12.14*
जोधपुर	गोमद राम	तकनीकी सहायक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम	10,000	*दै.न., 17.12.14*
सवाईमाधोपुर	कमलेश जैलिया अलीमुद्दीन इरफान गोल्डन	सभापति, नगर परिषद, सवाई माधोपुर कांस्टेबल, सहयोगी दलाल दलाल	15,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 28.12.14*

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

प्रशासन अपना रवैया बदले-मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सरकारी तंत्र से अपना रवैया बदलने के लिए कहा है। मेक इन इंडिया पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकारी सिस्टम जो नजरिया एबीसीडी अर्थात अवॉइड, बाईपास, कन्फयूज एवं डिलीट का रहा है। जिसे बदलकर रोड अवधारणा को काम में लाया जाए, रोड़ अर्थात रेस्पोंसिबिलिटी, ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और डिसीप्लेन की अवधारणा में काम किया जाए।

महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी साझीदारों को शामिल कर उनकी सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में नया आयाम जोड़ा है। *(न.नु., 31.12.14)*

गौरव पथ निर्माण को मिली मंजूरी

ग्रामीण गौरव पथ योजना के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहले साल में ही 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 3000 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाए जाएंगे। इनमें से सभी 33 जिलों व 186 विधानसभा क्षेत्रों के 2105 गांवों में सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूसुफ खान ने बताया कि योजना के तहत बनने वाली सड़कों की मजबूती पर खास जोर दिया जाएगा। *(दै.भा., 01.11.14)*

खत्म होंगे गैर जरूरी कानून

राज्य सरकार ऐसे कानून, अधिनियम और नियमों को खत्म करने जा रही है, जो आज के दौर में अप्रासंगिक हो चुके है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी घोषणा की।

ऐसे कानूनों की सूची बनाने और उनको खत्म करने के लिए सरकार ने सभी विभागों को करीब ढाई महीने का समय दिया है। इस प्रक्रिया के तहत करीब ढाई सौ संशोधनों और संशोधित कानूनों को वास्तविक या मौलिक कानून के अधीन कर एक किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार भी ऐसे कई कानूनों की समीक्षा कर रही है जिनकी आज के दौर में कोई प्रासंगिकता नहीं बची है या उन कानूनों से कई अड़चने खड़ी हो रही है। *(रा.प., 24.12.14, 25.12.14)*

अपने गांव पर हो गर्व-प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यदि करीब 800 सांसद 2019 तक अपने क्षेत्र के तीन-तीन गांवों का विकास करेंगे तो 2500 गांवों का विकास हो जाएगा। सांसदों को गांव चुनने की आजादी है, लेकिन वह गांव उनका खुद का या पत्नी का नहीं होना चाहिए। गांवों का विकास जनभागीदारी से भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा विधायक भी अपने क्षेत्र में आदर्श गांव बनाएं। ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे गांव वाले अपने गांव पर गर्व कर सके। वह खुद भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गांव गोद लेंगे। *(रा.प.एवं दै.भा., 12.10.14)*

विधायकों के लिए आदर्श ग्राम योजना

राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर विधायकों के लिए आदर्श ग्राम योजना की कवायद चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से राज्य में सात साल पहले चली दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी योजना राज्य के विधायकों के लिए भी लागू करने का सुझाव दिया था। प्रदेश में विधायक आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों के लिए विधायक कोष का कुछ हिस्सा सुरक्षित करने का विचार है। *(रा.प., 04.12.14)*

हर गांव को मिलेंगे 20 लाख

केन्द्रीय ग्रामीण विकास,पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार हर गांव को साफ-सफाई के लिए हर साल 20 लाख रुपए देगी। वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने के लिए गांवों को यह अतिरिक्त सहयोग दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में देश में करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस पर एक लाख 34 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न प्रकार की जैविक खाद और ऊर्जा के रूप में कूड़े-कचरे को धन में परिवर्तित करने की तकनीक का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाएगा।

(दै.न., 03.10.14)

खुद करें कागजात का सत्यापन

अब अपने कागजात के सत्यापन के लिए आपको राजपत्रित अधिकारियों के घरों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप खुद अपने कागजात का सत्यापन कर सकेंगे।

प्रदेश में यह व्यवस्था एक जनवरी 2015 से लागू हो जाएगी। यदि आपने अपने कागजात का सत्यापन गलत किया तो आपको सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।

(दै.न. एवं रा.प., 25.11.14)

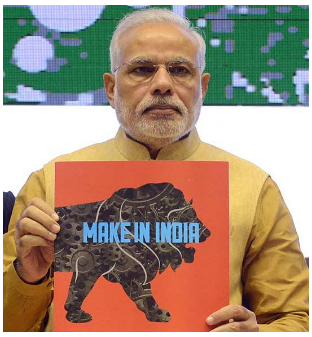

मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाना जरूरी

देश की आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने के लिए और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार कानूनों में बदलाव करेगी। इसके लिए सरकार में काम करने के तौर तरीको में भी बदलाव लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह ऐलान 'मेक इन इंडिया' अभियान की एक दिवसीय समीक्षा बैठक में की। उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों, और सरकारी अधिकारियों के विचारों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें सामूहिक और पारदर्शी निर्णय व्यवस्था का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत बनने वाले उत्पाद 'जीरो डिफेक्ट' हो और उनका पर्यावरण पर'जीरो इफेक्ट' हो। *(दै.भा., 30.12.14)*

सौर ऊर्जा नीति, प्रदेश बनेगा पावर हब

राज्य में 25000 मेगावाट की सोलर पावर उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना को क्रियान्वित करने के मकसद से राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2014 जारी कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, मुख्य सचिव राजीव महर्षि, उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव वीनू गुप्ता, ऊर्जा सचिव आलोक व बड़ी संख्या में उद्यमियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नीति का दस्तावेज जारी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति में सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया है। किसानों को सौर ऊर्जा नीति में पहली बार सीधे प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे बड़ा बदलाव आएगा। इस मौके पर खिंवसर ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति एक नए युग की शुरुआत है। इससे आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के सभी रूपों में पावर हब बन सकेगा। *(दै.भा., 09.10.14)*

बनेंगे 2700 मेगावाट के सोलर पार्क

राज्य सरकार ने जैसलमेर के परेवर गांव तथा जोधपुर के बाप तहसील में 2700 मेगावाट के तीन सोलर पार्कों को विकसित के लिए भूमि चिन्हित की है। भूमि को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए शुरुआती तौर पर सरकारी भूमि का चयन किया गया है। तीन सोलर पार्क विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार 340 करोड़ रुपए की सहायता देगी।

पार्क के विकसित होने के बाद निजी निवेशक को आंमत्रित किया जाएगा। आगामी पांच साल में 25000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के राज्य सरकार के लक्ष्य को देखते हुए विभाग ने अभी से प्राईवेट कंपनियों से सम्पर्क शुरू कर दिया है। निवेशक को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। सौर ऊर्जा उत्पादन के पार्कों को विकसित करने में करीब दो साल का समय लगेगा। *(दै.न., 17.12.14)*

कम नहीं हो रहा घाटे का बोझ

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां वित्तीय प्रबंधन के नुस्खे अजमाने के बाद भी अपने घाटे के बोझ को कम नहीं कर पा रही हैं। सभी बिजली कंपनियों का घाटा 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा होने की आशंकाओं से कंपनियां अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत में लगी हैं।

बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का मानना है कि बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन व खर्चों में कमी नहीं करने की वजह से लगातार घाटा बढ़ता गया। नई सरकार आने के बाद कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए विचार तो किया गया मगर कवायद कुछ भी नहीं की गई

(दै.न., 03.11.14)

राजस्थान डिस्कॉम वसूली में फिसड्डी

करोड़ों रुपए के घाटे से जूझ रहा राजस्थान डिस्कॉम एक ओर जहां 10-15 हजार रुपए का बिल बकाया होने पर आमजन के कनेक्शन काट रहा है वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमों पर करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद फील्ड अभियंता आंख मूंदे बैठे हैं। तीनों डिस्कॉम्स की बात की जाए तो आधा दर्जन महकमों पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है।

बकायादारों में जलदाय विभाग, पुलिस प्रशासन, नगरीय निकाय सहित अन्य कई विभागों में डिस्कॉम का बकाया है। लेकिन सबसे ज्यादा जुलाई 2014 तक जलदाय विभाग में 248 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बकाया थी। इसके बाद नगरीय निकाय और यूआईटी में 111 करोड़ रुपए बकाया थे।

(रा.प., 24.11.14)

प्रसारण निगम को लगा बड़ा झटका

प्रसारण तंत्र में इस साल होने वाले अनुमानित खर्च की स्वीकृति के लिए पेश वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की याचिका में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को बड़ा झटका लगा है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने याचिका में पेश गत वर्षों के खर्च के आंकड़ों की भी समीक्षा की, जिसमें राजस्थान डिस्कॉम्स से करीब 400 करोड़ रुपए की अधिक वसूली का खुलासा हुआ है। ऐसे में आयोग ने न सिर्फ प्रसारण निगम के प्रस्तावित खर्च में कटौती की है, बल्कि अधिक वसूली का पैसा डिस्कॉम्स प्रशासन को लौटाने के निर्देश दिए हैं। प्रसारण निगम को यह राशि पांच किश्तों में लौटानी होगी। *(रा.प., 30.10.14)*

प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई

घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने की योजना 24 इनटू 7 पॉवर फॉर ऑल पर विद्युत मंत्रालय की संयुक्त सचिव ज्योति अरोड़ा व राजस्थान के ऊर्जा सचिव संजय मलहोत्रा ने हस्ताक्षर कर प्रदेश में इस योजना को लागू किया। राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है, जिसे 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए चयनित किया गया है। इसके अन्तर्गत अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से 10240 मेगावाट सहित 14265 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। *(दै.भा., 14.12.14)*

खराब मीटर पर 5 फीसदी छूट

क्या आपका दो महीने से ज्यादा समय से बिजली का मीटर खराब है? बिजली कंपनी आपको औसत बिल थमा रही है? तो फिर क्या आपको हर बिल की राशि में 5 फीसदी छूट मिल रही है? यदि नहीं तो यह आपकी जागरूकता की कमी है। खराब मीटर नहीं बदलने की स्थिति में नियमानुसार 5 फीसदी की छूट बिल में दी जानी चाहिए।

राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग के एक नियम के पश्चात् तीनों विद्युत कंपनियों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन जयपुर डिस्कॉम द्वारा इसके आदेश संख्या जेपीडी-6/398 के अनुसार उक्त छूट का लाभ केवल उन मामलों में दिया जा रहा है, जो मीटर गत 12 माह या इससे अधिक समय से खराब पड़े हैं। आयोग ने उक्त आदेश पर आयोग के वैधानिक सेवा कोड का उल्लंघन मानते हुए गंभीरता से ऐतराज किया है और तीनों वितरण कंपनियों को इस कोड की पालना करते हुए अपने आदेश वापस लेने का निर्देश दिया।

धड़ल्ले से हो रहा अवैध जल दोहन

राज्य सरकार गिरते भू-जल स्तर पर रोक लगाने के लिए समय समय पर गाइड लाइन तैयार करती है, लेकिन भू-जल विभाग व जिला प्रशासन की नाकामी के चलते जगह-जगह अवैध बोरिंगों से जल का दोहन हो रहा है। जबकि जयपुर जिले को डार्क जोन घोषित किया गया है।

शहर में भू-जल दोहन के लिए जलदाय विभाग या निजी स्तर पर बोरिंग लगाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से अनुमति लेनी होती है, लेकिन न तो विभाग के अधिकारी ही इसकी अनुमति लेते हैं और न ही निजी स्तर पर कलेक्टर के यहां अनुमोदन के लिए आवेदन किए जाते हैं। इसके चलते नई कॉलोनियों के अलावा अपार्टमेंटों में धड़ल्ले से अवैध रूप से बोरिंग किए जा रहे हैं। *(दै.न., 15.10.14)*

2015-16 होगा जल संरक्षण वर्ष

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015-16 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल 13 से 17 जनवरी के बीच 'भारत जल सप्ताह' का आयोजन देश के हर जिले में किया जाएगा।

जल संकट को दूर करने के लिए हर जिले और गांव में जल संसाधनों का लेखा-जोखा तैयार कर 'हमारा जिला हमारा जल' योजना लाई जाएगी। जिले में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत वाले गांव को 'जल ग्राम' घोषित कर उसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। *(दै.भा., 23.11.14)*

पेयजल लाइनें बनी कोढ़ में खाज

जयपुर में पेयजल सप्लाई के दौरान जर्जर पाईपलाइनों से हो रही पानी की छीजत जलदाय विभाग के लिए कोढ़ में खाज बनी हुई है। शहर में सालों बाद भी पुरानी पाईपलाइनों से ही पेयजल सप्लाई हो रहा है। चारदीवारी सहित अधिकांश जगहों पर यह जर्जर अवस्था में है। इस वजह से पानी सप्लाई के दौरान लाखों लीटर पानी नालियों में व्यर्थ बह जाता है।

कई इलाकों में पेयजल पाईपलाइनें सीवर लाइन के पास से जुड़ी हैं, जिससे पाईपलाइन में लीकेज के कारण सीवर का पानी भी पेयजल में मिलकर उसे दूषित और जानलेवा बना रहा है। यह समस्या चारदीवारी में ज्यादा है। जलदाय विभाग को इन लाइनों को बदलकर पानी की बर्बादी और दूषित पानी की सप्लाई रोकने की खासी जरूरत है। *(दै.न., 02.11.14)*

कॉरपोरेशन संभालेगा पेयजल सिस्टम

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई का पूरा सिस्टम अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बजाय राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अधीन होगा।

कॉरपोरेशन का प्रशासनिक ढांचा विभिन्न महकमों के साथ संयुक्त रूप से तय होगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो वरिष्ठ आईएएस स्तर का होगा। कॉरपोरेशन पर पूरी तरह से निगरानी का कार्य स्वायत शासन विभाग का होगा। पेयजल व सीवरेज सिस्टम को पुख्ता करने के लिए विकास का संयुक्त प्लान बनेगा। *(दै.न., 11.12.14)*

हर जिले का होगा 'वाटर प्लान'

राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में पेयजल की गर्मियों में विकट स्थिति बन जाती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में वर्तमान व भविष्य के जल स्त्रोतों की संभावना तलाशने के साथ ही प्रत्येक जिले की ग्रामवार पेयजल स्थिति का आकलन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री किरण माहेश्वरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिलों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए जिले के जलस्त्रोतों को विकसित कर उनमें पानी की आवक सुनिश्चित की जाएगी। समस्यागत इलाकों में पेयजल को लेकर नई योजनाओं के लिए खाका भी तैयार किया जाएगा। *(दै.न., 12.11.14)*

रामगढ़ बांध को मिले खास पैकेज

जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने लोकसभा में जयपुर की पेयजल आपूर्ति से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर से बीसलपुर परियोजना से सप्लाई होने वाले पेयजल की अब आसपास के कस्बों में लगातार मांग बढ़ती जा रही है।

रामगढ़ बांध से पूर्व में शहर की चारदीवारी में भी पानी की सप्लाई होती थी। इसका पानी आस-पास के गांवों में सिंचाई के भी काम आता था। पर्यटन के लिए भी यह खास जगह थी। लेकिन अब इसमें पानी की आवक नहीं होने से सूखा पड़ा है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि रामगढ़ परियोजना को विशेष आर्थिक पैकेज देकर पुनः चालू करवाया जाए। इससे न केवल पीने के पानी की समस्या दूर होगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। *(दै.भा., 10.12.14)*

तेजी से गिरता भूजल स्तर

गत कुछ सालों से प्रदेश में अच्छी बरसात होने के बावजूद लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। इससे डार्क जोन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में हो रहे अतिदोहन से औसतन हर साल तीन मीटर भूजल स्तर में गिरावट आती जा रही है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड की जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही स्थिति रही तो आने वाले एक दशक बाद प्रदेश में पानी का संकट पैदा होने वाला है।

प्रदेश के 237 ब्लॉक में से 140 ब्लॉक अतिदोहन की श्रेणी में हैं। इसके अलावा 50 ब्लॉक में जलदोहन चिंताजनक स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अतिदोहन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। प्रदेश में 162 ब्लॉक भूजल दोहन के लिहाज से प्रतिबंधित की श्रेणी में है, इनकी संख्या बढ़कर अब 207 होने वाली है। महज 25 ब्लॉक ठीक स्थिति में बताए जा रहे हैं। *(दै.न., 03.10.14)*

मेवाड़ विकलांग सेवा ने बढ़ाए कदम

चित्तौड़गढ़ जिले में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र ने पहल करते हुए क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के विकलांगजनों को एक मंच प्रदान किया है। तीन दिसम्बर 2010 को विश्व विकलांग दिवस पर महिलाओं सहित 185 विकलांगजनों ने इसमें भाग लेकर अपनी ताकत का अहसास कराया था। अब विकलांग सेवा संस्थान का गठन करते हुए उसका पंजीयन भी कराया गया है। मंच से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 600 विकलांग जुड़ चुके हैं।

साईट सेवर्स के सहयोग से 'कट्स' द्वारा संचालित राजस्थान सामाजिक समावेशन कार्यक्रम से उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने ही विश्व विकलांग दिवस के पूर्व निम्बाहेड़ा व कपासन में कार्यकारिणी का गठन किया गया। संस्थान द्वारा निकट भविष्य में विशेष योग्यजनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और सरकारी स्तर पर अन्य सुविधाओं के लिए पैरवी की जाएगी।

आम आदमी बीमा योजना शुरू

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की एक लाख 43 हजार 504 महिलाओं को आम आदमी बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

योजना के तहत लाभान्वित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के परिवारों की सामान्य व प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए व दुर्घटना में मृत्यु और पूर्णतया अपंग होने पर 75 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। बीमित महिलाओं के कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले दो बच्चों को 100 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

(दै.न., 16.12.14)

तलाक के बाद पत्नी को भी हिस्सा

केन्द्र सरकार ने विवाह कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित कानून के तहत तलाक की स्थिति में पति की अचल सम्पत्ति में से पत्नी व बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। इसके लिए केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने विवाह कानून (संशोधन) बिल पर कैबिनेट नोट तैयार किया है।

इस पर मंत्रालयों से राय मांगी गई है। फीडबैक मिलने पर इसको अंतिम मंजूरी के लिए केबिनेट में भेजा जाएगा। पूर्व यूपीए सरकार ने भी इस बिल को पारित कराने का प्रयास किया था, लेकिन यह लोक सभा में अटक गया था। अब नई सरकार मंत्रालयों की राय के बाद इसमें बदलाव कर मंजूरी के लिए सदन में रखेगी। *(दै.भा., 17.11.14)*

हर ग्राम पंचायत में होंगे सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में भामाशाह योजना के तहत पहला कार्ड संपत देवी को सौंपा। पटेल मैदान में इस योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं का पैसा इस कार्ड से मिलेगा। इस योजना में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

अभी इससे पेंशन, स्कॉलरशिप, राशनकार्ड और मनरेगा योजना को जोड़ा जा चुका है। स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ड का लाभ महिलाओं को मिल सके, इसके मद्देनजर हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सेवा केन्द्र तथा शहरों में पर्याप्त संख्या में केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार द्वारा घोषित बीमा योजनाओं के लाभों को भी इस कार्ड से जोड़ा जाएगा

(रा.प., 16.12.14)

निःशुल्क लगेगा पेंटावेलेंट टीका

शिशुओं को पांच गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह टीका बच्चों में डिप्थीरिया, परटच्यूसिस, टिटनेस, हैपेटाइटिस–बी एवं हिमेफिलिस इंफ्लूएंजा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

जयपुर के जेकेलोन, जयपुरिया, कांवटिया और बनीपार्क अस्पताल में यह ट्रायल के रूप में शुरू किया जा चुका है। सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा।

(रा.प., 02.11.14)

बाल विवाह पर सख्त प्रतिबन्ध लगे

संयुक्त राष्ट्र में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में दुनियाभर के देशों की सरकारों से बाल विवाह पर सख्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील की है।

इसके लिए बाल अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों से मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभिन्न देशों में प्रति वर्ष करीब डेढ़ करोड़ बच्चियों को जबरन विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। करीब 70 करोड़ लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। भारत में बाल विवाह की दर सबसे ज्यादा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बच्चियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। *(दै.न., 23.11.14)*

बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा भीलवाड़ा जिले में चाइल्ड लाइन सेवा संचालित की जा रही है। चाइल्डलाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर बाल श्रमिकों से जुड़ी शिकायतों पर अक्टुबर माह में बाल कल्याण समिति व मानव तस्करी विरोधी इकाई के तत्वावधान कार्रवाई करते हुए कुंभा सर्किल के पास एक भोजनालय से तीन व कृषि उपज मण्डी परिसर स्थित केंटीन से पांच बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया।

बच्चों के अभिभावकों को पाबंद किया गया कि वें बच्चों से 18 साल की उम्र होने से पहले मजदूरी नहीं कराएंगे। नियोजकों के खिलाफ पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

जन स्वास्थ्य

अब सबको मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ

अमरीका और अन्य विकसित राष्ट्रों की तरह भारत भी सबको स्वास्थ्य बीमा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो बड़े वादे किए थे। पहला, जन धन योजना के तहत हर किसी का बैंक खाता खुलवाना और दूसरा सबको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना।

ऐसा होगा स्वास्थ्य बीमा का स्वरूप

- *देश के सभी नागरिक इसके दायरे में होंगे*
- *50 जरूरी दवाएं इसमें शामिल की जाएंगी*
- *आयुर्वेद व होम्योपैथी की 30 विकल्पीय दवाऐं भी होंगी।*
- *सभी तरह की मेडिकल जांच का पैकेज*
- *गरीबी रेखा से नीचे वालों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जबकि बाकी श्रेणी के लोगों को आय के हिसाब से न्यूनतम प्रीमियम देना होगा।*

पहला वादा पूरा करने के बाद स्वास्थ्य बीमा पर काम तेज हो गया है। सरकार जनवरी से सबको स्वास्थ्य बीमा देने के लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन की घोषणा कर सकती है।

इस मिशन के तहत प्रत्येक देशवासी का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा, ताकि उसे मुसीबत के वक्त सभी तरह की दवाइयां और इलाज मुफ्त मिल सके। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय पहले ही फैसला ले चुका है। मिशन का प्रस्ताव अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है और वह योजना के मॉडल को तैयार करने में जुटा है। संभावना है कि गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। *(रा.प., 24.11.14)*

सड़क सुरक्षा

टेस्ट ड्राइविंग में नहीं चलेगी कृपा

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट-ड्राइव में अब आरटीओ अधिकारियों की कृपा नहीं चलेगी। राजधानी में गुजरात की तर्ज पर ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (एडीटीटी) बनाया जा रहा है। जिसमें कम्प्यूटर चालक की गलतियां पकड़ेगा। परिवहन विभाग सलाहकार नियुक्त कर पीपीपी मॉडल पर यह ट्रैक बनाएगा।

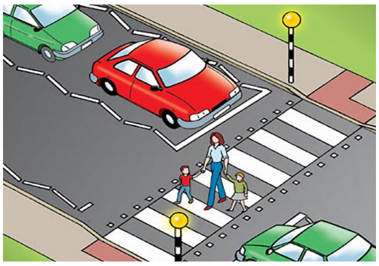

यह ट्रेक 'आठ' या 'एस' की आकृति में बनाया जाना है। ट्रैक के दोनों तरफ छोटे-छोटे पोल पर सेंसर लगे होंगे। टेस्ट के दौरान वाहन पर भी एक यंत्र लगाया जाएगा, जिससे सेंसर वाहन चालक की गलतियां पकड़ेगा। टेस्ट पूरी तरह से पारदर्शी होगा। वाहन चालकों को कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। इससे परिपक्व व योग्य वाहन चालकों को ही लाइसेंस मिल सकेगा। *(रा.प., 04.12.14)*

निवेशक शिक्षा

सेबी ने जारी किए ट्रेडिंग के नियम

बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं प्रमोटर का परिवार इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आएगा। इनसाइडर की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

सेबी ने डीलिस्टिंग नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। डिलिस्टिंग के लिए कम से कम 25 फीसदी शेयरधारकों की मंजूरी लेना जरूरी होगा। सेबी ने डीलिस्टिंग रेगुलेशन को भी अनुमति दी है डीलिस्टिंग की समय सीमा 76 दिन अथवा छह माह कर दी गई है जो कि पहले 137 दिन थे। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति जानबूझकर डिफाल्टर साबित होता है तो वह बाजार से पैसा नहीं जुटा सकते हैं। सेबी ने कहा है कि वह ई-आईपीओ लाने पर भी विचार कर रही है। *(दै.भा., 20.11.14)*

मानक सेवा

मानकों में हो रहा व्यापक बदलाव

किसी भी ब्राण्ड को उसके गुणवत्ता मानक से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ब्राण्ड उत्पाद का विकल्प बन चुके हैं। मौजूदा मानकों के स्तर में विश्वभर में सुधार हो रहा है। उद्यमियों को चाहिए कि वे प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मानकों की कड़ाई से पालना करने और उससे भी बेहतर उत्पाद तैयार करें, तभी प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' सपने को पूरा किया जा सकेगा।

यह विचार जयपुर स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक एसोसिएशन सभागार में विश्व मानक दिवस पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से 'मानक प्रतिस्पर्द्धा का समान अवसर देते हैं' विषयक संगोष्ठी में उभरे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और हिन्दुस्तान साल्ट लि. के सीएमडी आर.के.टण्डन ने बताया कि श्रेष्ट उत्पाद की गांरटी मानक ही है। अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में टिकने के लिए मानक के समकक्ष उत्पाद बनना जरूरी है, क्योंकि उत्पादों का उपयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। *(रा.प., 15.10.14)*

दूरसंचार सेवाएं

जांच सकेंगे फोन की खराबी

टेलीफोन पर डायल टोन नहीं आने पर उपभोक्ता सीधे बीएसएनएल शिकायत केन्द्र पर शिकायत दर्ज कराते हैं। लाइनमैन पहुंचने पर पता चलता है कि लाइन में फाल्ट ही नहीं है, बल्कि टेलीफोन की पेटी खराब है। टेलीफोन की पेटी सुधारने के लिए अलग स्टाफ है। बेवजह लाइनमैन को चक्कर काटने पड़े।

ऐसे हालात से बचने के लिए बीएसएनएल ने नई सुविधा के रूप में छह अंकों का नम्बर 127161 जारी किया है। इसे अपने टेलीफोन पर डायल करने के तत्काल बाद रिसीवर रखना होगा। रिंग टोन नहीं बजने की स्थिति में ही लाइन में खराबी होगी। *(रा.प., 21.12.14)*

उपभोक्ता फैसले

प्याज के घटिया बीज देना भारी पड़ा

अलवर जिला मंच में किसान शिवलाल व धर्मसिंह की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने वर्ष 2008 में दो किलो प्याज का बीज 1250 रुपए में खरीदा था, लेकिन प्याज अच्छा नहीं उगा। मामले की सुनवाई के बाद मंच ने राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा बीज विक्रेता हरियाली किसान बाजार को आदेश दिए थे कि वह किसान शिवलाल व धर्मसिंह को 27 हजार रुपए बतौर हर्जाना और तीन हजार रुपए परिवाद खर्च अदा करे।

उपभोक्ता मंच के फैसले के खिलाफ बीज विक्रेता हरियाली किसान बाजार ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। मामले की सुनवाई पर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से कहा गया कि बीज उनके द्वारा तैयार नहीं थे। जबकि विक्रेता ने निरीक्षण दल में विशेषज्ञ के शामिल नहीं होने का तर्क दिया। आयोग ने राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा कही गई बात को सही मानते हुए उपभोक्ता मंच द्वारा लगाए गए हर्जाने व परिवाद खर्च की पूरी राशि 30 हजार रुपए विक्रेता हरियाली किसान बाजार को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, विक्रेता पर अपील करने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। विक्रेता को आदेश की पालना के लिए 30 दिन का समय दिया गया। *(रा.प., 04.12.14)*

गलत सीट दी, एयरलाइंस पर 20 लाख का जुर्माना

बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के बावजूद 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को इकोनोमी क्लास की सीट देना यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी लुत्पहंसा को काफी भारी पड़ा। तमिलनाडू राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को सेवा का दोषी करार देते हुए उपभोक्ता शिवप्रकाश कोयनका को 20 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए है।

मामले के अनुसार शिवप्रकाश गोयनका ने 10 अक्टूबर, 2010 में फ्रेंकफर्ट से चेन्नई के लिए बिजनेस क्लास में टिकट बुक कराया था। लेकिन फ्लाइट में उन्हें इकोनोमी क्लास में सीट दी गई। वैसे इसके बदले एयरलाइंस ने उन्हें 1.15 लाख रुपए (1500 यूरो) का चैक दिया। लेकिन गोयनका ने चैक लौटाते हुए कंपनी को कानूनी नोटिस थमा दिया। गोयनका का तीन बार हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, इसके चलते वह व्हील चेयर पर रहते हैं। गोयनका का कहना था कि खराब स्वास्थ के कारण ही उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट कटाया था। उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई पर एयरलाइंस कंपनी को सेवा में त्रुटी का दोषी माना और 20 लाख रुपए गोयनका को बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। *(रा.प., 06.11.14)*

खास समाचार

उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए सजग रहे - जिला कलेक्टर

शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता अपने कर्तव्य के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तभी भ्रामक विज्ञापनों से बच सकते हैं। यह विचार जिला रसद कार्यालय एवं कट्स के संयुक्त तत्वावधान में चित्तौड़गढ़ स्थित कट्स मानव विकास केन्द्र के परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर भ्रामक विज्ञापनों से मुकाबला विषय पर आयोजित जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने व्यक्त किए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए तहसील स्तर पर जन-जागरूकता बैठकों के माध्यम से संदेश पहुंचाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी विरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि आज के बदलते हुए बाजार परिदृश्य में हम चारों ओर से विज्ञापनों के मायाजाल से घिरे हैं। इस मायाजाल से बचने के लिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व दायित्वों के प्रति सशक्त करना जरूरी है ताकि वे भ्रामक विज्ञापनों में न फंसे। कट्स मानव विकास केन्द्र के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि किस प्रकार आम उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों से बच सकता है। गोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता चांदमल गर्ग ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी देकर लाभान्वित किया तथा वरिष्ठ नागरिक मंच के सचिव आर.सी.डाड ने खाद्य वस्तुओं में हो रही मिलावट पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल दिया।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।